# मोदी सरकार को कांग्रेस ने हर मोर्चे पर फेल कहा

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मोदी सरकार की जमकर आलोचना की गई और कहा गया कि पार्टी हर उस तबके का साथ देगी, जिसे सरकार जबरिया दबाने की कोशिश कर रही है। अपने निवास पर दिन में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्वर में जो स्वर नहीं मिलाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सोनिया ने कहा उसे डराया और धमकाया जाता है और भय का माहौल पैदा किया जाता है। सरकार का यह रुख रा[illegible]ओं के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि कमजोर तबके, छात्रों और नागरिक संगठनों, मीडिया के प्रति भी देखने को मिला है।

**मेक इन इंडिया निवेश लाने में विफल रहा :** सोनिया ने कहा कि सिर्फ नोटबंदी का ही मामला नहीं है और भी कई मोर्चों पर यह सरकार असफल साबित हुई है। कांग्रेस की शीर्ष नेता ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया पर वो भी निवेश लाने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है और पूरे देश का किसान परेशान है और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता गुलामनबी आजाद ने पी चिदम्बरम और मुकुल वासनिक के साथ पत्रकारों को बताया कि कार्यसमिति ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को निराशाजनक माना है। कार्यसमिति का मानना है कि यह नारों और प्रचार की सरकार है, जो टीवी पर हीरो ले[illegible] जमीन पर जीरो है।

## संकट का सामना कर रहा उत्पीड़ित वर्ग

पार्टी अध्यक्ष सोनिया ने कहा, 'सबसे बुरी बात है कि महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं अन्य उत्पीड़ित वर्ग संकटपूर्ण समय का सामना कर रहे हैं। जो लोग अन्य मत या विचार रखते हैं उनके जीवनयापन एवं खानपान की आदतों पर हमला किया जा रहा है।'

## विकास में भारी गिरावट आई : मनमोहन सिंह

मनमोहन ने कहा कि नोटबंदी के कारण भारत के आर्थिक विकास में भारी गिरावट आयी है। 'भारत के गत वित्त वर्ष की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2016-17 के जीडीपी आंकड़े कुछ दिन पहले जारी किए गए। मुख्यतः नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी घोषणा के कारण।'

## संगठनात्मक चुनावों को भी मंजूरी

गुलाम नबी आजाद ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक चुनावों के कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'हम 2019 के चुनावों से बहुत दूर नहीं हैं। हमें भारत की मूल आत्मा और विचार की रक्षा को तैयार रहना चाहिए जिसे यह सरकार मिटाने का प्रयास कर रही है।'

# आईटीआई के लिए सीबीएसई की तर्ज पर बनेगा परीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली में मंगलवार को अपने मंत्रालय की तीन साल की उपलब्धियों की बुकलेट जारी करते केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी।

नई दिल्ली। कौशल विकास मंत्री राजीव प्रतीप रूड़ी ने बताया कि सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण लेने वाले लगभग 23 लाख छात्रों की परीक्षा लेने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तर्ज पर एक बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। मानव संसाधन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है।

रूड़ी ने अपने मंत्रालय की तीन साल की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ युवाओं की रोजगारपरकता में भी वृद्धि कर रही है। सरकार हाथ से काम करने वाले लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साधारण तौर पर आईटीआई में वे छात्र प्रशिक्षण लेते हैं, जो आठवीं और दसवीं कक्षा पास करने बाद कहीं प्रवेश ले पाते हैं। आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन बच्चों के सामने आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। सरकार ने इस समस्या के समाधान के विशेष उपाय किए हैं और फिलहाल इन बच्चों की योग्यता को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से प्रमाणित कराया जाता है।

## एमडी, एमएस में 50 फीसद आंतरिक कोटे पर फैसला आज

नई दिल्ली (एसएनबी)। एमडी, एमएस आदि पीजी डिग्री कोर्स में 50 फीसद सीट यूनिवर्सिटी के स्नातकों के लिए रिजर्व रखने की नियम पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बीएचयू व एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

कोर्ट ने दोनों विवि के साथ-साथ एमसीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया। जस्टिस अशोक भूषण और दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि इस पर आदेश बुधवार को सुनाया जाएगा। दोनों विश्वविद्यालयों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णय और भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों का उल्लंघन होता जिनमें संस्थाओं को 50 फीसद सीटों पर अपनी संस्थाओं से प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी।

# 'सेना में महिलाओं को धीरे-धीरे लड़ाकू भूमिका में लाएं'

नई दिल्ली। महिलाओं को युद्ध के मोर्चे पर लगाने की सेना की योजना का कई वर्गों ने समर्थन किया है, जबकि कुछ का मानना है कि इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे किया जाना चाहिए। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के पूर्व महानिदेशक और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बीके चोपड़ा ने इस कदम को अच्छी शुरुआत बताया।

उन्होंने कहा, 'आधुनिक सेना के लिए केवल संख्या मायने नहीं रखती। पिछले 70 वर्षों में सेना बदली है और महिलाएं भी अब पहले जैसी नहीं हैं। शारीरिक रूप से वे पुरुषों की तुलना में अलग हो सकती हैं, लेकिन वह कोई मुद्दा नहीं है और प्रशिक्षण के दौरान इसका ख्याल रखा जा सकता है।' लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी ने कहा कि संगठन (सेना) सर्वोच्च है और किसी भी तरह की बाध्यता का संज्ञान लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया 15-20 वर्षों तक चलनी चाहिए, ताकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए। ■ भाषा


**J.K. Cotton Limited**

CIN: U17111UP1924PLC000275

Registered Office: Kamla Tower, Kanpur-208 001, U.P., India

Telephone: (0512)2371478-481 Fax: (0512) 2332665

E-mail: harshit@jkcotton.com Website: www.jkcotton.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 94th Annual General Meeting of the Company will be held on **Wednesday, 26th July, 2017** at 12:30 PM at Auditorium of Dr. Gaur Hari Singhania Institute of Management & Research, Kamla Nagar, Kanpur – 208 005 to transact the business contained in the Notice which is being sent to all the Shareholders individually. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company will remain closed from **Wednesday, 19th July, 2017 to Wednesday, 26th July, 2017** (both days inclusive). Further, the cut-off date for the purpose of 'remote e-voting' as required pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 has been fixed as **Wednesday, 19th July, 2017.**

By Order of the Board

Sd/-

HARSHIT GUNANI

COMPANY SECRETARY

Place : Kanpur

Date : 5th June, 2017


7/6/2017.